बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 114

आयातित अर्थशास्त्री

चौथे और अंतिम अर्थशास्त्री भी अटलांटिक पार की दुनिया में लौट रहे हैं। विरल आचार्य बहुत जल्दी अरविंद सुब्रमण्यन, रघुराम राजन और अरविंद पानगड़िया की तरह पश्चिमी जगत में लौट जाएंगे। मीडिया में आई टिप्पणियों में देश को पराजित पेश किया गया है लेकिन कोई भी उतना चिंतित नहीं है जितनी चिंता राजन की शिकागो वापसी के वक्त देखने को मिली थी। उस चिंता को भी उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जो आचार्य ने केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को लेकर दिए अपने मशहूर भाषण में जताई थी। लेकिन लोगों ने तो बतौर वित्त मंत्री दिए गए अरुण जेटली के उस बयान पर भी अपना नजरिया नहीं रखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार की गलतियों में से एक विदेशों से अर्थशास्त्रियों को लाना भी थी।

जब भी देश से कोई शीर्ष अर्थशास्त्री बाहर जाता है तो इसका नुकसान देश को होता है। परंतु इस पर चर्चा से पहले इस संभावना पर विचार करते हैं कि विशेषज्ञ गलत भी हो सकते हैं। आचार्य की अकादमिक काबिलियत और केंद्रीय बैंक के कामकाज में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया लेकिन रिजर्व बैंक में उनके प्रदर्शन पर उठे सवालों का उन्हें जवाब देना चाहिए। उनकी निगरानी में आरबीआई का वृहद आर्थिक विश्लेषण मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि दर के मामले में गलत साबित हुआ। इन दोनों का अतिरंजित अनुमान लगाया गया। इसी कारण ब्याज दर नीति के मामले में भी उनकी सलाह गलत थी। उन्होंने आरबीआई द्वारा की गई दो हालिया कटौतियों का विरोध किया था।

सवाल सांस्कृतिक पहलुओं का भी है। भारतीयों के साथ कारोबार कर रहे विदेशी पाते हैं कि भारतीय असहमत होने पर कभी सीधे ना नहीं कहते। इसके बजाय वे बात बदल देते हैं या अप्रत्यक्ष संकेत देने लगते हैं। यह अमेरिका से एकदम उलट है जहां अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सीधे नकार का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार के साथ काम करने वाले लोग भी उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहते। अगर आप रिजर्व बैंक के गवर्नर या डिप्टी गवर्नर हों तो आपको आम नागरिक के समान अभिव्यक्ति की आजादी हासिल नहीं होती। तब मतभेदों पर आंतरिक बातचीत ही होती है। ऐसे में जब राजन और आचार्य ने खुलकर अपनी बातें कहीं तो इसे ठीक नहीं माना गया। नोटबंदी जैसे मसले पर जहां राजन को अपनी राय साफ तौर पर रखनी थी वहां वह प्रतिकूल सलाह देने के बाद साथ हो गए।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

फिर भी इन अर्थशास्त्रियों की सेवा लेना गलती नहीं थी। राजन की बैंकों की साफ-सफाई की प्रतिबद्धता की वजह से ही परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा हुई और गड़बड़ियां सामने आईं। दूसरा, राजन और उनके डिप्टी (बाद में उत्तराधिकारी) ऊर्जित पटेल में तालमेल नहीं था यह सब जानते हैं लेकिन इन दोनों ने ही आरबीआई का नया मौद्रिक ढांचा तैयार किया और मुद्रास्फीति नियंत्रण को मौद्रिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य बनाया। यह सोच अंतरराष्ट्रीय थी लेकिन वाईवी रेड्डी और बिमल जालान जैसे पुराने देसी गवर्नरों से एकदम उलट थी।

वित्त मंत्रालय में अरविंद सुब्रमण्यन के कई नीतिगत नुस्खों की सरकार ने अनदेखी कर दी। परंतु वस्तु एवं सेवा कर की आदर्श दर पर उनकी रिपोर्ट को परोक्ष स्वीकृति मिल गई। कई दरों के उनके विरोध को भी उनकी विदाई के बाद आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। सुब्रमण्यन को सरकार की वार्षिक आर्थिक समीक्षा के विश्लेषण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने वृद्धि के आधिकारिक आंकड़ों पर सवाल उठाया है, उसके बाद संभवत: उनको अवांछित ही माना जाएगा।

नीति आयोग में अरविंद पनगड़िया जल्दी आए और दो वर्ष पहले उन्होंने उससे दूरी भी बना ली। उन्हें प्रधानमंत्री के साथ उतना समय बिताने का मौका नहीं मिला जितनी उन्होंने अपेक्षा की होगी। शायद वृहद आर्थिक नीति को लेकर उनकी सुधारवादी सोच मोदी सरकार से मेल नहीं खाती थी। मोदी सरकार की रुचि कार्यक्रमों और परियोजनाओं में अधिक थी। वह मुद्दों पर आधारित सुधार में रुचि रखती थी, मिसाल के तौर पर चिकित्सा शिक्षा सुधार। यहां नीति आयोग ने अपनी भूमिका भी निभाई लेकिन तटीय आर्थिक क्षेत्र जैसे पानगड़िया के बड़े विचार फलीभूत नहीं हो सके।

आज, जबकि वृद्धि दर में गिरावट है और हर दिशा से वृहद आर्थिक चुनौतियां आ रही हैं, क्या सरकार को हार्वर्ड शिक्षित अर्थशास्त्रियों की राय से लाभ होता? शायद होता लेकिन पुराने रिकॉर्ड पर ध्यान दें तो शायद उनकी बातों को अधिक तवज्जो ही नहीं मिली होती।

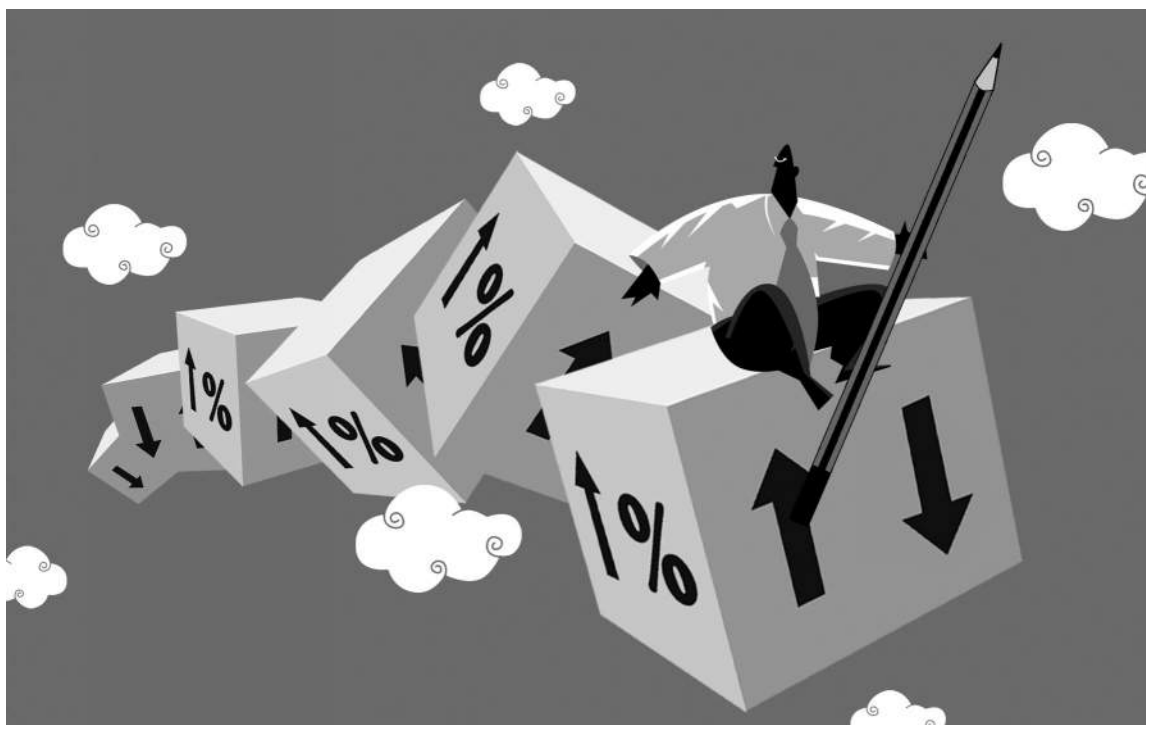

बिनय सिन्हा

अंकेक्षक का पेशा और मौजूदा हालात

अंकेक्षण रिपोर्ट केवल एक विचार होती है। उसे किसी चीज का प्रमाण या गारंटी नहीं मानना चाहिए। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **देवाशिष बसु**

इस महीने के आरंभ तक अंकेक्षण उन पेशों में से एक था जिनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी अधिनियम के तहत हर कंपनी को अंकेक्षण कराना होता है। पहेली की शुरुआत इसके बाद होती है। अपेक्षा होती है कि अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी का मालिक/अंशधारक करे, न कि प्रबंधन। परंतु हम सभी जानते हैं कि हर निजी कंपनी में और अधिकांश सरकारी कंपनियों में प्रवर्तक परिवार का प्रबंधन और अंशधारिता दोनों पर नियंत्रण होता है। बहुत कम ऐसी सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं जहां प्रवर्तक के पास बहुलांश हिस्सेदारी नहीं होती और केवल प्रबंधन ही अंकेक्षक का चयन करता है। बाहरी अंशधारकों की अंकेक्षक नियुक्त करने या बदलने में कोई खास रुचि नहीं होती। अंकेक्षण का पहला आधारभूत नियम यही है कि प्रबंधन को खिझाने का काम नहीं करें।

दूसरा आधारभूत नियम अंकेक्षकों के लिए राहत लाता है। सन 1896 में किंग्सटन कॉटन मिल्स कंपनी के मामले में निर्णय देने वाले लॉर्ड जस्टिस लोप्स के शब्द उधार लें तो आशा की जाती है कि वे निगरानी का काम करें, न कि शिकार करने का। तीसरा नियम चीजों को और आसान बना देता है: अंकेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बही खातों को लेकर सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर पेश करेंगे। अंकेक्षण रिपोर्ट केवल एक विचार होती है, न कि किसी चीज का प्रमाणपत्र अथवा गारंटी। इन तीनों नियमों के आधार पर ही पीढ़ियों से अंकेक्षकों के प्रभाव का आकलन किया जाता रहा है।

यह केवल छोटी कंपनियों और छोटे अंकेक्षकों का मामला नहीं है। सन 2000 के दशक के आरंभ में जब टाटा फाइनैंस बड़े पैमाने पर सटोरिया बाजार की गतिविधियों, सर्कुलर लेनदेन और अन्य संदेहास्पद सौदों में शामिल थी, तब टाटा ने ए फर्गुसन को खास अंकेक्षण के लिए नियुक्त किया था। वरिष्ठ साझेदार वाई एम काले की निगरानी में तैयार फर्गुसन रिपोर्ट में टाटा के निदेशकों को क्लीन चिट नहीं दी गई। टाटा ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया और अपने राजस्व के लिए काफी हद तक टाटा पर निर्भर फर्गुसन ने काले को नौकरी से निकाल दिया।

व्यवस्था में अपराध को सुधारने की इजाजत है लेकिन केवल कागज पर। ऐसे मामलों में आप भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के समक्ष पेशेवर के गलत आचरण की शिकायत कर सकते हैं। परंतु मैं बहुत सारे ऐसे मामलों के बारे में भी जानता हूं जहां आईसीएआई की अनुशासन परिषद अंकेक्षक के साथ मिल गई। जानकारों को पता है कि यह कैसे काम करता है। ऐसे में कई अच्छे सनदी लेखाकार अंकेक्षण के काम से दूर ही रहते हैं। अधिक नैतिक लोग हताश महसूस करते हैं।

इस माह के आरंभ में एक नाटकीय घटनाक्रम में अक्सर सुसुप्त रहने वाली सरकार की दो ताकतवर शाखाओं ने इस खेल के नियम बदल दिए। 11 जून को कंपनी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट की शरण में जाकर आईएलऐंडएफएस के अंकेक्षकों डेलॉयट हस्किंस और सेल्स ऐंड बीएसआर ऐंड एसोसिएट्स पर पांच वर्ष तक प्रतिबंध लगाने की मांग की। ऐसा उनकी आईएलऐंडएफएस प्रबंधन के साथ कथित मिलीभगत के चलते किया गया। बीएसआर अंकेक्षण कंपनियों बड़े नेटवर्क केपीएमजी का हिस्सा है। मंत्रालय का यह कदम एक ऐसे संस्थान के शानदार प्रदर्शन के बाद उठाया गया है, जिसे हम भुलाते रहते हैं। वह संगठन है गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)। संगठन ने आरोप लगाया कि आईएलऐंडएफएस मामले में अंकेक्षकों ने पूर्व निदेशकों के साथ मिलकर गलतियों की सूचना छिपाई। इन बातों का असर पड़ना तय था। प्राइस वाटरहाउस ऐंड कंपनी एक और उदाहरण है जिस पर प्रतिभूति बाजार नियामक ने 2018 में दो वर्ष का प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध सत्यम घोटाले में उसकी भूमिका के चलते लगाया गया था। कंपनी ने जून में रिलायंस कैपिटल के सांविधिक अंकेक्षक की भूमिका छोड़ दी। उसका आरोप था कि कंपनी उसे स्वतंत्र आकलनकर्ता की अपनी भूमिका नहीं निभाने दे रही थी।

ये घटनाएं ऐसे समय पर हुई हैं जब राष्ट्रीय वित्तीय नियमन प्राधिकार (एनएफआरए) के अधीन अंकेक्षण, लेखा और वित्तीय मानकों के नियमन में सांस्थानिक बदलाव किए जा रहे हैं। आईसीएआई ने सन 2010 से 2017 तक एनएफआरए का भरपूर विरोध किया। उसने दलील है कि वह एक विश्वस्तरीय नियामक है और एनएफआरए अतिरिक्त बोझ बन जाएगा। एक से अधिक नियामकीय संस्थाएं होने से सक्षम कर्मचारियों की कमी होगी। परंतु आम धारणा है कि आईसीएआई स्वनियमन में नाकाम रहा है।

बरकरार रहे गतिशीलता

अंकेक्षक केवल अंशधारकों की नहीं बल्कि नियामकों, सरकार, निवेशकों, बैंकरों और व्यापक तौर पर जनता की मदद करते हैं। ऐसे में मौजूदा साफ-सफाई की आवश्यकता थी और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह सिलसिला केवल हाई प्रोफाइल अंकेक्षकों तक सीमित न रह जाए। पहला कदम होगा ऐसे हजारों छोटे सनदी लेखाकारों को सशक्त बनाना जो स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं लेकिन प्रवर्तकों या प्रबंधन की दया पर हैं। मैं निजी रूप से जानता हूं कि ऐसे सभी लेखाकार शुरुआत में पेशेवर काम करना चाहते हैं। वे अंकेक्षण में उलझना ही नहीं चाहते। उन्हें देखना होगा कि एनएफआरए की सफलता उनके पेशे में स्वच्छता और निष्पक्षता लाती है।

दूसरा कदम होगा अंकेक्षण के मानकों को बेहतर बनाना। मिसाल के तौर पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मूल कंपनी के अंकेक्षकों को अनुषंगी कंपनियों के बही खातों के लिए भी जिम्मेदार बनाने पर विचार कर रहा है। अन्य देशों ने भी धीरे-धीरे निगरानी वाले रूपक से दूरी बनाई है और बेहतर दायित्व की ओर बढ़े हैं। तीसरा कदम होगा वित्तीय कंपनियों के अंकेक्षकों के लिए विशेष मानक तय करना। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अंकेक्षक दूसरों की भारी भरकम धनराशि से जुड़ा काम करते हैं। लॉर्ड डेनिंग ने सन 1958 में अंकेक्षकों के बारे में लिखा था, 'अपने काम को उचित ढंग से अंजाम देने के लिए उसके पास जिज्ञासु मस्तिष्क होना चाहिए, न कि बेईमानी की आशंका।' हालांकि मुझे संदेह ही है कि अगर डेनिंग और लोप्स आज होते तो वे शायद यही कहते है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में अंकेक्षकों को शिकारी की भूमिका में होना चाहिए और उनके दिमाग में जांच परख के अलावा संदेह भी भरा होना चाहिए।

जेपी नड्डा को भली-भांति जानते पहचानते हैं भाजपा कार्यकर्ता

जगत प्रकाश नड्डा को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और भाजपा की बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) इकाई इस बात को लेकर बेहद प्रसन्न है कि उनके यहां के नेता को इतनी बड़ी सफलता मिली है। आम धारणा यही है कि छह महीने बाद जब वह पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाएंगे (ऐसा होना ही है क्योंकि भाजपा के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान ही नहीं है) तब भी वह अमित शाह की निगरानी के अधीन ही काम करेंगे।

महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद भाजपा के सामने अगले 18 महीनों के दौरान कुछ ही चुनावी चुनौतियां हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि शाह की अनुपस्थिति पार्टी पर बहुत भारी नहीं पड़ेगी और ज्यादा नुकसान नहीं होगा।

भाजपा जितने वर्षों तक सत्ता में रही है, उस दौरान उसके चार अध्यक्ष रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब कुशाभाऊ ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष थे। ठाकरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रतिनिधि थे। ठाकरे एक प्रचारक थे और लगता नहीं कि निकट भविष्य में भाजपा किसी प्रचारक को पार्टी का अध्यक्ष बनाएगी। बंगारू लक्ष्मण दलित थे और उनको सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग के तौर पर पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन वह रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तीसरा नाम जन कृष्णमूर्ति का है। इन सभी की पार्टी को चलाने की अपनी-अपनी शैली थी। जब आदर्श चुनने की बारी आएगी तो नड्डा शायद वेंकैया नायडू की शैली के सबसे करीब होंगे। वह नायडू जैसे चतुर भले ही नहीं हों लेकिन उनकी कार्य शैली वैसी ही व्यापक है।

उन्होंने भाजपा में एक कार्यकर्ता और संगठन के व्यक्ति के रूप में लंबे समय तक काम किया है और यह खूबी उनमें वहीं से आई है। अपने आसपास देखिए। आपको उस पीढ़ी के और उस स्तर पर ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे। पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव जैसे जिन नेताओं को सरकार में ऊंचे पद मिले हुए हैं, उन्हें पार्टी संगठन का कोई खास अनुभव नहीं है। नड्डा को 40 वर्ष का संगठनात्मक अनुभव है जो उनके समकालीनों में शायद ही किसी के पास हो। उन्होंने सन 1980 के दशक में हिमाचल विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के लिए पहली बार छात्र संघ का चुनाव जीता। वह चुनाव बराबरी पर छूटा था और उन्हें अध्यक्ष पद अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ साझा करना पड़ा। यही कारण है कि वह आधे कार्यकाल तक ही पद पर रह सके। बाद में वह एबीवीपी के अखिल भारतीय संगठनात्मक सचिव बन गए और आगे चलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। उस वक्त हिमाचल के अन्य बड़े नेता प्रेम कुमार धूमल कहीं दृश्य में ही नहीं थे। वह दिल्ली में लोकसभा में थे और नड्डा हिमाचल भाजपा के एक अन्य दिग्गज शांता कुमार के साथ विधानसभा में थे।

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

> अपनी अखिल भारतीय नियुक्तियों के कारण नड्डा भाजपा संगठन को करीब से जानते हैं। वह अपनी वाक कला से भीड़ भले ही न जुटा पाएं लेकिन कार्यकर्ता उनको अच्छी तरह जानते हैं और दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के कद से कहीं ऊपर निकल गए हैं। जेपी नड्डा भाजपा के ऐसे नेता हैं जिन पर नजर रखी जानी चाहिए

सन 1998 का हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव बदलाव लेकर आया। नरेंद्र मोदी भाजपा के महासचिव बन चुके थे। भाजपा के पास पिछली विधानसभा में केवल आठ सीट थीं। चुनाव के बाद पार्टी 31 सीट जीत चुकी थी। पिछली विधानसभा में नड्डा नेता प्रतिपक्ष थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन पार्टी ने धूमल को मुख्यमंत्री बनाया। संभव है इस नियुक्ति में मोदी की भूमिका रही हो। नड्डा अपनी निराशा को पचा गए और धूमिल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। साथियों के साथ उनके रिश्ते को एक उदाहरण से परिभाषित किया जा सकता है। उनके सहयोगियों के मुताबिक कार्यकर्ताओं से मिलने पर वह कहते, 'काम के अलावा कोई काम बताओ।'

जब भाजपा हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई तो नड्डा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के अधीन हो गए। गडकरी ने उन्हें राज्यसभा में भिजवाया और उनकी पदोन्नति की। आगे चलकर वह भाजपा की सर्वोच्च संस्था यानी पार्टी के संसदीय बोर्ड के सचिव बन गए। इस बोर्ड में केवल आठ सदस्य हैं। वह सात वर्ष से अधिक समय तक इस पद पर रहे।

अपनी अखिल भारतीय नियुक्तियों के कारण नड्डा भाजपा संगठन को करीब से जानते हैं। वह अब किसी के लिए खतरा भी नहीं है। वह अपनी वाक कला से भीड़ भले ही न जुटा पाएं लेकिन कार्यकर्ता उनको अच्छी तरह जानते हैं और दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के कद से कहीं ऊपर निकल गए हैं। लेकिन कौन जानता है, शायद एक दिन वह लक्ष्य भी हासिल हो जाए। जेपी नड्डा भाजपा के ऐसे नेता हैं जिन पर नजर रखी जानी चाहिए।

कानाफूसी

स्वच्छता पर जोर

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी योजना बनाई है। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री के उद्धरणों की 20,000 प्रतियां प्रकाशित कराई हैं। सूत्रों के मुताबिक जलशक्ति मंत्रालय जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता, जल संसाधन एवं गंगा सफाई मंत्रालय शामिल हैं, वह इन पुस्तिकाओं को वितरित कराने की योजना बना रहा है। संसद में इस सप्ताह के आरंभ में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के दौरान प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और स्वच्छता अभियानों को आगे बढ़ाने की अपील की थी। माना जा रहा है कि रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात में भी वह इन्हीं मसलों पर बात करेंगे।

'पबजी कूटनीति'

देश के शहरी युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए मोबाइल गेम पबजी ने अब दूसरे देशों में भी अच्छी खासी पैठ बना ली है। एक ओर जहां माता-पिता और नीति निर्माता इस हिंसात्मक खेल के नकारात्मक प्रभाव से परेशान हैं, वहीं मोबाइल गेम का गढ़ माने जाने वाले देश ताइवान ने इसका प्रयोग आर्थिक रिश्ते मजबूत करने में किया है। बुधवार को भारत में ताइवान के शीर्ष अधिकारी यानी प्रतिनिधि राजदूत थ्यान चुंग क्वांग ने युवाओं के एक समूह से चर्चा में कहा कि भारत के लोग इस खेल में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ताइवान अपने गेमिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रचार कर रहा है और भारत के छोटे शहरों में 60 दिनों तक ताइवान के मोबाइल गेमों का प्रचार किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि हाथों और आंख के बीच सही तालमेल और तेज विकसित होती संस्कृति राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने आशा जताई कि भारतीय युवा जीतना जारी रखेंगे।

आपका पक्ष

वन क्षेत्र बढ़ने से प्रदूषण में राहत

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में बताया है कि पिछले एक वर्ष में देश के वन क्षेत्र में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.39 प्रतिशत हिस्सा हरित क्षेत्र के तहत है। संसद में प्रश्न काल के दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यदि किसी विकास कार्य के लिए एक पेड़ काटा जाता है तो उसके बदले उसी स्थान या किसी अन्य स्थान पर 3 -4 पौधे लगाए जाते हैं। संबंधित आंकड़ों में किसी तरह की गलती से बचने के लिए नियमित अंतराल के बाद सैटेलाइट से चित्र लिए गए, जिससे पेड़ तथा फसलों के बीच विभेद किया जा सके। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल क्षेत्रफल के दिन प्रति दिन आबादी बढ़ रही है जिसके चलते निवास, खेती एवं अन्य कारणों के लिए वन क्षेत्र तबाह किये जा रहे हैं। इसलिए देश में केवल 25 फीसदी से कम वन क्षेत्र बचे हैं एवं देश को पर्यावरण संतुलन के लिए लगभग 8 प्रतिशत वन क्षेत्र की और आवश्यकता है। देश में वन क्षेत्र बढ़ने के मुकाबले सड़क पर गाड़ियां तेजी से बढ़ रही हैं इसलिए दिन प्रति दिन दोपहिया और निजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इससे बड़े और छोटे शहरों में ट्रैफिक जाम की परेशानी के साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जहरीली हवा वाले देशों में 14 शहर भारत के हैं और इसमें से 4 शहर उत्तरप्रदेश से हैं। पिछले साल मई के महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया था। भारत में वर्ष 2017 में वायु प्रदूषण के कारण 12 लाख लोगों की मौत हुई है। इसलिए सरकार को पौधरोपण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पेड़ काटने वालों के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए, जिससे नागरिकों को बढ़ते प्रदूषण से राहत मिल सके।

पिछले एक वर्ष में भारत के वन क्षेत्रफल में करीब एक प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है

निशांत त्रिपाठी, नागपुर, महाराष्ट्र

दिल्ली में भी लागू हो आयुष्मान योजना

दिल्ली सरकार को भी आयुष्मान भारत योजना लागू करनी चाहिए। यह स्वास्थ्य योजना देश के करीब 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मुहैया कराती है। दिल्ली सरकार तर्क दे रही है कि आयुष्मान योजना से दिल्ली के कम ही लोगों को लाभ होगा और इस योजना से बेहतर दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना है। सवाल यह है कि अगर किसी योजना से एक भी व्यक्ति को लाभ पहुंचे तो सरकारों को उस योजना को अपनाना चाहिए। किसी योजना से कम लोगों को लाभ मिलने का हवाला देकर उसे लागू नहीं करने का फैसला उचित नहीं है। इसलिए दिल्ली सरकार को अविलंब आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करना चाहिए।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।